बिगड़ती कानून–व्यवस्था

धनखड़ ने एक ट्वीट करके बताया कि प्रधानमंत्री ने 'राज्य में कानून–व्यवस्था की चिंताजनक हालत पर क्षोभ जताया है।' उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी एक ट्वीट टैग करते हुए लिखा है, 'राज्य में जारी हिंसा, लूटपाट और हत्याओं पर मैं अपनी गंभीर चिंता आपसे साझा करता हूं।'

सोनल ।।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राजनीतिक हिंसा का मामला तूल पकड़ गया है, जिसमें अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर और राज्य में बिगड़ती कानून–व्यवस्था को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ से बात की है। धनखड़ ने एक ट्वीट करके बताया कि प्रधानमंत्री ने 'राज्य में कानून–व्यवस्था की चिंताजनक हालत पर क्षोभ जताया है।' उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी एक ट्वीट टैग करते हुए लिखा है, 'राज्य में जारी हिंसा, लूटपाट और हत्याओं पर मैं अपनी गंभीर चिंता आपसे साझा करता हूं।'

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी बंगाल में राजनीतिक हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां हिंसा से पीड़ित पार्टी कार्यकर्ताओं के परिजनों से मिलने पहुंच गए हैं। पश्चिम बंगाल के साथ ही अन्य तीन राज्यों और एक केंद्र शासित क्षेत्र में भी चुनाव नतीजे घोषित हुए।

बंगाल को छोड़कर कहीं से भी हिंसा की खबरें नहीं आईं। चुनावों के दौरान हिंसा का मकसद आम तौर पर वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित करना होता है। बंगाल में यह हिंसा राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों द्वारा एक–दूसरे को सबक सिखाने की प्रवृत्ति के रूप में सामने आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तक राजनीतिक हिंसा के लिए दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। इसे राजनीतिक रंग दे दिया गया है।

ममता बनर्जी ने अपने समर्थकों से राजनीतिक हिंसा रोकने की अपील तो की, लेकिन लगे हाथ इसका दोष बीजेपी पर मढ़ दिया, जबकि जरूरत इसे रोकने की साझा अपील करने की है। दोनों ही दलों की ओर से यह पहल होनी चाहिए। उन्हें इस बारे में अपने समर्थकों को स्पष्ट संदेश देना चाहिए। इस बात को लेकर भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि इसे रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। ऐसा करके ममता अपनी प्रशासनिक कुशलता साबित करेंगी। यह भी याद रखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का लंबा इतिहास रहा है।

ममता को अपने इस कार्यकाल में इस धब्बे को भी मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। यह भी भूलना नहीं चाहिए कि राज्य में महामारी तेजी से फैल रही है। सरकार को अपनी पूरी ताकत इसे रोकने में लगानी चाहिए। खुद ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि उनकी सरकार की प्राथमिकता कोरोना महामारी को काबू में करने की होगी, जो बिल्कुल ठीक है। वह सुनिश्चित करें कि राज्य सरकार अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल इसे रोकने में करे।

जीवन की संभावना

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

हम सब जानते हैं जल है तो कल है। जहां जल नहीं है वहां जीवन नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक यह खोजने में लगे हुए हैं कि पृथ्वी के अतिरिक्त और किन ग्रहों पर जल है जिससे वहां जीवन की संभावना खोजी जा सके। पुराणों के अनुसार इस संसार का निर्माण जल के बिना नहीं हो सकता है और प्रलय काल में सब कुछ जल में ही विलीन हो जाता है, इस जल को एकार्णव कहा गया है। यदि हम यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे के सिद्धांत पर ध्यान दें हमें अपने शरीर और ब्रह्मांड में जल की मात्रा का साम्य दिखाई देगा। हमारी पृथ्वी का तीन चौथाई हिस्सा जल से ढका हुआ है और मनुष्य के शरीर का तीन चौथाई भाग पानी से बना हुआ है। इसके अलावा इस संसार के पालनहार भगवान विष्णु भी जल में स्थित है।

संपादकीय

घट रही है फर्टिलिटी रेट

लगता है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण के कड़े नियमों के पैरोकारों ने चीन से कोई सबक नहीं सीखा है। वे ऐसी बेतुकी मांग तब कर रहे हैं, जब देश में बिना किसी कड़े कानून और नियमों के कुल फर्टिलिटी रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में 1994 में कुल फर्टिलिटी रेट 3.4 थी, जो 2015 में घटकर 2.2 रह गई। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, देश के 19 राज्यों में परिवारों में औसतन दो या उससे कम बच्चे हैं, जो रिप्लेसमेंट रेट के करीब है और जो जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए जरूरी है। नहीं तो दो–तीन दशकों में भारत भी खुद को चीन की स्थिति में खड़ा पाएगा। इन देशों में तीव्र विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा के प्रसार और वर्कफोर्स में महिलाओं की बढ़ी भागीदारी के कारण ऐसा हुआ है। यानी विकास से बड़ा कोई गर्भनिरोधक नहीं है। मजे की बात यह है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े कानून की इस बेतुकी बहस में डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी देश की आबादी में 65 फीसदी से अधिक युवाओं और वर्किंग आबादी की मौजूदगी की चर्चाएं भुला दी गई हैं। बहस तो इस पर होनी चाहिए कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ लेने के लिए युवाओं को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण रोजगार देने के लिए क्या किया जा रहा है।

असम सरकार इस साल जनवरी के बाद से दो से अधिक बच्चों वाले परिवारों को राज्य में सरकारी नौकरी और स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवारी के लिए अयोग्य घोषित करने का फैसला कर चुकी है।

चीन की भूल

लेखकः आनंद प्रधान।।

असम के नए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने राज्य में दो बच्चे की नीति पर और कड़ाई बरतने के लिए कुछ अपवादों के साथ उन परिवारों को कई सरकारी सब्सिडी और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित करने का भी संकेत दिया है, जिनके निश्चित कट–ऑफ डेट यानी तय तारीख के बाद दो से अधिक बच्चे होंगे। इससे पहले असम सरकार इस साल जनवरी के बाद से दो से अधिक बच्चों वाले परिवारों को राज्य में सरकारी नौकरी और स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवारी के लिए अयोग्य घोषित करने का फैसला कर चुकी है।

इधर, उत्तर प्रदेश से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि राज्य सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है, जिसमें असम की तरह ही दो से अधिक बच्चे पैदा करने वाले परिवारों को सरकारी नौकरियों, जन–कल्याण योजनाओं और लाभों से वंचित करने का प्रस्ताव है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े उपायों की मांग के साथ एक जनहित याचिका दाखिल कर रखी है।

देश में इस मुद्दे पर तीखी बहसें नई नहीं हैं। आमतौर पर यह मांग अनुदार दक्षिणपंथी

राजनीतिक खेमे की तरफ से उठती रही है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े और दंडात्मक उपायों के समर्थक अधिकांश पार्टियों में रहे हैं। 90 के दशक से राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओड़िशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक आदि राज्यों में दो से अधिक बच्चे पैदा होने पर पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी के अयोग्य ठहराए जाने के कानून बनाए गए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में दो से अधिक बच्चे होने पर परिवारों को सरकारी नौकरियों से भी वंचित करने के कानून पहले से हैं। इमरजेंसी के दौरान जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर जिस तरह से जबरन नसबंदी और दूसरे डराने–धमकाने वाले सख्त तौर–तरीके नाकाम रहे, वह इतिहास भी किसी से छुपा नहीं है।

हैरानी की बात यह है कि देश में दो बच्चों की नीति ऐसे वक्त में बन रही है, जब 80 के दशक से जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुख्यात रहे चीन में 'एक बच्चा (वन चाइल्ड)' नीति के कारण पैदा हुई विसंगतियों और समस्याओं ने उसे एक जनसांख्यिकीय आपदा के कगार पर पहुंचा दिया है। चीन की जनगणना के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि उसकी आबादी में एक ओर 60 वर्ष से अधिक उम्र के बूढ़ों की संख्या बढ़ रही है तो दूसरी ओर, युवा और वर्किंग लोगों की संख्या घट रही है।

इसलिए चीन सरकार ने हाल में 'एक बच्चा (वन चाइल्ड)' की अपनी नीति में एक और बड़ा बदलाव करते हुए परिवारों को तीन बच्चे पैदा करने की छूट दी है। इससे पहले चीन ने 2016 में दो बच्चे पैदा की अनुमति दी थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी जनसंख्या में महिलाओं की कुल फर्टिलिटी रेट में गिरावट और उसके रिप्लेसमेंट रेट से भी नीचे चले जाने के रुझान में कोई फर्क नहीं आया है। जनसंख्या में स्थायित्व के लिए महिलाओं की फर्टिलिटी रेट 2.1 रहनी चाहिए, जिससे एक परिवार खुद को दोहरा सके और जनसंख्या में वर्किंग युवाओं की संख्या स्थिर हो सके।

लेकिन चीन में 80 के दशक की अदूरदर्शी और अवैज्ञानिक जनसंख्या नीति के कारण फर्टिलिटी रेट 1970 के 5.8 से घटकर 2015 में 1.6 रह गई, जो रिप्लेसमेंट रेट से भी कम है।

सूडोकु नवताल-5407

मध्यम

6	9			7	4		8	
	8	5	6	2			4	9
7						6		3
	3	9	5				1	
1				8				5
	6				2	9	3	
4		7						2
8	2			5	9	1	7	
	1		2	3			5	8

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5406 का हल

6	5	3	9	1	7	2	8	4
9	1	8	2	6	4	3	7	5
7	4	2	5	3	8	1	9	6
3	7	1	6	9	2	4	5	8
8	6	9	1	4	5	7	2	3
5	2	4	8	7	3	9	6	1
2	9	5	4	8	1	6	3	7
4	3	6	7	5	9	8	1	2
1	8	7	3	2	6	5	4	9

अपना ब्लॉग

अब अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन

मोहन। चीन इस नीति को पिछले पांच साल में दो बार बदलने और पहले दो बच्चे पैदा करने और अब तीन बच्चे पैदा करने की छूट देने का ऐलान कर चुका है, लेकिन कुल फर्टिलिटी रेट 2015 के 1.6 से गिरकर 2020 में 1.3 रह गई। चीन अब अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन और कई सुविधाएं देने की बात कर रहा है। चीन ही नहीं, दुनिया के कई और विकसित देश भी महिलाओं की कुल फर्टिलिटी रेट में गिरावट के रुझान और उसके रिप्लेसमेंट रेट से भी नीचे चले जाने के कारण चिंतित हैं। मानवीय विकास सूचकांक में सबसे ऊपरी पायदान पर खड़े दुनिया के अधिकांश विकसित और अमीर देशों में महिलाओं की कुल फर्टिलिटी रेट 1.2 से लेकर 0.98 तक पहुंच चुकी है, जो रिप्लेसमेंट रेट से काफी कम है। इसलिए इन देशों में वृद्धों की संख्या बढ़ और वर्किंग आबादी घट रही है। इससे उनकी अर्थव्यवस्थाओं के लिए कई परेशानियां खड़ी हो रही हैं।